दिसंबर, **2022** माह के दौरान इस मंत्रालय की कुछ प्रमुख उपलब्धियां/पहलें इस प्रकार हैं:

1. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने 26 दिसंबर, 2022 को अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले अग्निवीरों को राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र देने के लिए अपनी लचीली समझौता ज्ञापन स्कीम के तहत सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. महिला उदयमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

i. 'महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्ट-अप्स' (डब्ल्यूईई) परियोजना को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमज़ेड) की ओर से एमएसडीई के साथ साझेदारी में डच जेशल्शेफ्ट फ़र इन्टरनेशनल जुशामनेरबीट (जीआईज़ेड) द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है, ताकि भारत में महिला-नीत उद्यमों की आधारभूत संरचना की स्थिति में सुधार किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य महिला सूक्ष्म-उद्यमियों के लिए प्रायोगिक इंक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रमों को चलाना है, जिससे उन्हें महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और देश के 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों में नए व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा उद्यमों को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

'हर एंड नाउ' नामक शीर्षक के अंतर्गत, डब्ल्यूईई परियोजना सफल महिला उद्यमियों की वृत्तान्तों को साझा करने और समाज में जेंडर रोल और मानदंडों पर मानसिकता को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए एक फिल्म और मीडिया अभियान चला रही है। दिसंबर तक, इंक्यूबेशन और त्वरण समर्थित दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत इस परियोजना के तहत 900 से अधिक महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान किया गया है।

ii. एमएसडीई की एक परियोजना जिसका उद्देश्य छह पवित्र शहरों में उदयमशीलता विकास, संभावित और मौजूदा उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, पिछड़ा वर्ग के युवाओं आदि की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता कार्यकलापों को उत्प्रेरित करना है। यह परियोजना पुरी, बोधगया, कोल्लूर, वाराणसी, हरिद्वार और पंढरपुर में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की कुल संख्या 7,185 है, जिनमें से 4,535 महिलाएं हैं।

3. एमएसडीई के ई-ऑफिस संस्करण को दिनांक 02-12-2022 को संस्करण 7.x में अपग्रेड कर दिया गया था। साथ ही जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के लिए दिनांक 07-12-2022 को एसटीक्यूसी प्रमाणन हेतु एमएसडीई की वेबसाइट प्रस्तुत की गई थी।

4. कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कुशल भारत मिशन के अंतर्गत भारत के युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत 12 दिसंबर, 2022 को 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) आयोजित किया। स्थानीय युवाओं को

शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से अपने करियर को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करने के लिए मेले का हिस्सा बनने हेतु कई स्थानीय व्यवसायों को आमंत्रित किया गया। देश में प्रति माह शिक्षुता मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें चयनित व्यक्तियों को नए कौशल प्राप्त करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक वृत्तिका मिलती है। शिक्षुता को कौशल विकास का सबसे स्थायी मॉडल माना जाता है, और इसे कुशल भारत मिशन के अंतर्गत भरी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और इस मिशन को पूरा करने के लिए, पीएमएनएएम को प्रतिष्ठानों तथा छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यह भाग लेने वाली कंपनियों में मौजूद विभिन्न अवसरों पर युवाओं को जागरूकता भी प्रदान कर रहा है।

5. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) उप-थीम: पिलर 2 के अंतर्गत कौशल विकास : समवेशी मानव विकास के लिए नोडल मंत्रालय था। उप-थीम 6: कौशल विकास को दो भागों अर्थात कौशलीकरण तक पहुंच: कौशलीकरण इकोसिस्टम में विस्तार और कौशलीकरण में गुणवत्ता: 5-7 जनवरी, 2023 को आयोजित मुख्य सचिव के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेतु कौशलीकरण, में विभाजित किया गया था।

6. व्यापक समावेशन और व्यापक राज्य स्तरीय परामर्श के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो समूहों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक समूह में 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे। कौशलीकरण ट्रैक तक पहुंच के लिए ओडिशा अग्रणी राज्य था और कौशलीकरण में गुणवत्ता ट्रैक के लिए कर्नाटक को अग्रणी राज्य के रूप में सौंपा गया था। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वर्चुअल और वास्तविक बैठक आयोजित की गई। दोनों ट्रैकों पर वर्चुअल बैठक में भाग लेने के अलावा, मैंने ने बेंगलुरु में कौशलीकरण और भुवनेश्वर में कौशलीकरण में गुणवत्ता हेतु ट्रैक-एक्सेस के लिए आयोजित वास्तविक बैठक में भाग लिया। कौशलीकरण में पहुँच और कौशलीकरण में गुणवत्ता पर दो विस्तृत अवधारणा नोट तैयार किए गए और नीति आयोग के साथ साझा किए गए, जिसमें वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियों, समाधानों और कार्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। एमएसडीई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित हितधारकों के लिए कार्रवाई बिन्दुओं के साथ पूरी प्रक्रिया पर एक प्रस्तुति तैयार की गई थी। इसे अंतिम रूप देने से पहले कैबिनेट सचिव और नीति अयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी।

7. आईटीआई के 500 अनुदेशकों/प्रशिक्षकों के लिए 5 दिनों का ऑफ़लाइन (आवासीय आधारित) उदयमशीलता विकास-संबंधी-प्रशिक्षकों-का-प्रशिक्षण-कार्यक्रम, रोजगार और जीवन कौशल का आयोजन डीजीटी द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उदयमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर, 2022 माह में आईटीआई के 213 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

8. राष्ट्रीय उदयमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) की स्कीम में उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य जेएसएस कर्मचारियों और प्रशिक्षकों की

क्षमता निर्माण, सलाह और सहायता के माध्यम से जन शिक्षण संस्थानों में उद्यमशीलता की भावना को सृजित करना, पोषित करना और बढ़ावा देना है।

9. नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के जेएसएस कर्मचारियों और प्रशिक्षकों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और जीवन कौशल संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के 45 बैच आयोजित किए गए थें। जेएसएस के कुल 1103 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

10. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए हैं, जबकि पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) नियोजन से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है। उद्योग संबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से मंत्रालय ने स्वायत्त उद्योग-नीत वाले निकायों के रूप में 37 क्षेत्र कौशल परिषदों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है ताकि राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) संरेखित जॉब रोलों [अर्हता पैक (क्यूपी)] और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या विकसित किया जा सके, कौशल अंतर अध्ययन का संचालन किया जा सके और आकलन एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणित किया जा सके।

11. 5जी सहित दूरसंचार क्षेत्र के लिए कौशल विकास पहलों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 27.12.2022 को सचिव, दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय (एमओसी) और सचिव, कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की संयुक्त अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक से निम्नलिखित बिंदु उभर कर सामने आए:

i) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टीएसएससी) को 5जी सहित दूरसंचार क्षेत्र में प्रासंगिक और महत्वाकांक्षी जॉब रोल विकसित करना है। इसके अलावा, टॉप-अप अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आईटीआई पास-आउट उम्मीदवारों के लिए उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए विकसित किया जाना है।

ii) मुख्य प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों का एक जीवंत इकोसिस्टम टीएसएससी द्वारा डीओटी, एमओसी के अंतर्गत बीएसएनएल, बीबीएनएल, आदि जैसे निकायों के सहयोग से अवसंरचना और ज्ञान का परस्पर उपयोग करके विकसित किया जाना है।

iii) राष्ट्रीय उदयमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के सहयोग से टीएसएसस द्वारा विकसित किए जाने वाले कार्यकर्ता-उद्यमी का एक पूल बनाने के लिए अनुकूलित अर्हता पैक (क्यूपी) को विकसित किया जाना है।

iv) दूरसंचार क्षेत्र में उन देशों में प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति भेजने के लिए अन्य देशों के साथ प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते (एमएमपीए) का लाभ उठाया जाना है।

v) प्रयोगशालाओं, उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), आदि की स्थापना में दूरसंचार क्षेत्र से उद्योगों के साथ सहयोग कि संभावनाओं, का पता लगाया जाएगा।

12. युवाओं को उपयुक्त कौशल के साथ सशक्त बनाकर और उन्हें सही अवसरों तक पहुंच प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-जर्मन संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक दिनांक 07-12-2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार-विमर्श का उद्देश्य जर्मन मानकों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वीईटी के लिए एक मानक तंत्र को संस्थागत बनाना था। कौशल अंतराल का आकलन करने के लिए एक कौशल मैपिंग अभ्यास किया जाएगा और उसी के आधार पर भारतीय श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स और कौशल उन्नयन कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इस बैठक के दौरान, दोनों भागीदार देशों ने नियोक्ता संबंधता के लिए एक ढांचा स्थापित करने पर चर्चा की और इस संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस तरह कुशल प्रमाणित श्रमिक आर्थिक विकास में भाग ले सकते हैं, संबंधित संस्थानों के साथ जिनके पास प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जी2जी, जी2बी और बी2बी संबंध के माध्यम से दोनों देशों में प्रशिक्षण प्रदाताओं की पारस्परिक मान्यता, को भी पूरा कर सकते हैं।

13. कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष विभाग (इसरो) में तकनीकी कर्मचारियों का कौशल उन्नयन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, और इस सहयोग से, इसरो तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के अंतरिक्ष उद्योग में नवीनतम रुझानों और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी क्षमता बढ़ाने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए इसरो के तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करना है। आगामी पांच वर्षों में, 4000 से अधिक इसरो तकनीकी कर्मचारी सदस्य भारत भर में स्थित कई एनएसटीआई के कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।